

घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 115- मंगलवार 24- फरवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,ड्राक एंजीवन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028



विकसित छत्तीसगढ़ का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट

24 फरवरी 2026, मंगलवार | दोपहर 12:30 बजे

छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रादेशिक न्यूज़ चैनलों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण



आ रहा है छत्तीसगढ़ का बजट



दिल्ली विधानसभा-सचिवालय को बम ब्लास्ट की धमकी

खालिस्तानी ग्रुप ने ईंग्लैंड में लिखा-दिल्ली बनेगा खालिस्तान,आर्मी-एयरफोर्स स्कूल को श्रेत मिली



नई दिल्ली,23 फरवरी 2026। दिल्ली विधानसभा भवन, दिल्ली सचिवालय और लाल किले को बम ब्लास्ट में उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार को खालिस्तानी ग्रुप का धमकी वाला ईमेल भेजा गया। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुईं, विधानसभा भवन की सर्चिंग की गई। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड सर्च में जुटी लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं, लाल किला की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इससे पहले दिल्ली स्थित धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और दिल्ली फायर सर्विस की टीमें स्कूल पहुंची थी। पूरा कैम्प खाली कराया गया। जांच में कुछ भी नहीं मिला था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ईमेल में दिल्ली बनेगा खालिस्तान की धमकी दी गई थी। लिखा था कि अगले 3 दिनों के भीतर आर्मी स्कूल, लाल किला और मेट्रो स्टेशनों पर विस्फोट हो सकते हैं। ईमेल में विधानसभा, आर्मी स्कूल और लाल किले के लिए अलग-अलग समय भी लिखा था। धमकी के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सभी स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर एंटी-सैबोटज जांच,रैडम चेकिंग और यात्रियों की तलाशी की जा रही है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीमों को लाल किला, दिल्ली सचिवालय और विधानसभा परिसर सहित कई संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है।

पश्चिम बंगाल की जनता के लिए पीएम ने लिखी चिट्ठी सीएए का जिक्र,घुसपैठ पर लगाम

नई दिल्ली,23 फरवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम हिंदी और बांग्ला भाषा में एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सीएए का जिक्र करते हुए घुसपैठ पर लगाम,राज्य के विकास, कानून-व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों पर अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने पत्र की शुरुआत जय मां काली के उपनाम के साथ की। उन्होंने लिखा-अब बस कुछ ही महीने में पश्चिम बंगाल का भाग्य सुनिश्चित हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह आपके सोचें-समझे फैसले पर निर्भर करता है। उन्होंने लिखा कि मेरे सोनार बंगाल के सपने देखने वाला हर एक जवान, बुढ़ा और महिलाएं आज बहुत पीड़ा में हैं। उनकी पीड़ा से आज मेरा हृदय भी व्यथित है। इसलिए मैंने मन की गहराइयों से एक संकल्प लिया है, पश्चिम बंगाल को विकासित और समृद्ध बनाने का संकल्प। उन्होंने आगे लिखा- पिछले 11 वर्षों में देशवासियों के आशीर्वाद को ताकत बनाकर मेरी सरकार ने जनकल्याण और समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।



देश की पहली आतंकवाद-विरोधी नीति जारी

केंद्र ने प्रहार नाम दिया,इसमें कहा...आतंकवादी इंटरनेट के जरिए भर्तियां और जिहाद का महिमामंडन करते हैं...

नई दिल्ली,23 फरवरी 2026। गृह मंत्रालय ने सोमवार को भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति जारी की। इसका नाम है प्रहार- PRAHAAR। आठ पेज की इस नीति में आतंकी हमलों को रोकने पर खास जोर दिया गया है। साथ ही खतरे के मुताबिक तेज और संतुलित कार्रवाई की बात कही गई है। केंद्र ने पहले पेज पर इंटरडक्शन और PRAHAAR का फूल फॉर्म बताया है।

इंटरडक्शन में लिखा है...कुछ पड़ोसी देशों ने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया है। फिर भी भारत आतंकवाद को किसी खास धर्म,जाति,देश या सभ्यता से जोड़कर



नहीं देखता। नीति में कहा गया है कि आतंकी इंटरनेट का इस्तेमाल आपस में संपर्क, संगठन में भर्ती और जिहाद के महिमामंडन के लिए करते हैं। सरकार ने

नीति में भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई है। इसमें कहा गया है कि आतंकवाद को किसी भी धार्मिक, जातीय या वैचारिक आधार पर सही नहीं ठहराया

नीति में लिखा...विदेश से भारत में हिंसा फैलाने की साजिशें रची गई...

नीति में कहा गया है कि विदेशों की जमीन से काम करते हुए आतंकियों ने भारत में हिंसा फैलाने की साजिशें रची हैं। उनके संचालक (हैडलर) डोन समेत नई तकनीकों का इस्तेमाल कर पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और हमलों को अंजाम देने में मदद करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि आतंकी संगठन अब तेजी से संगठित आपराधिक गिरोहों की मदद ले रहे हैं, ताकि लॉजिस्टिक सपोर्ट और भर्ती के जरिए भारत में आतंकी हमले कर सकें। प्रचार,आपसी संपर्क,फंडिंग और हमलों को दिशा देने के लिए ये आतंकी समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं।

जा सकता। सरकार ने प्रहार में कहा है कि भारत हर तरह के आतंकवाद की हमेशा कड़ी निंदा करता रहा है। नीति में आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने

के लिए एक व्यवस्थित और खुफिया जानकारी पर आधारित स्ट्रक्चर बताया गया है। सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में कोयले आधारित कारखानों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

इन्हें शिफ्ट करने और 300km के दायरे में नए प्लांट खोलने पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली,23 फरवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कोयले से चलने वाले उद्योगों को एनसीआर से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने दिल्ली से 300 किलोमीटर के अंदर नए कोयला आधारित पावर प्लांट खोलने पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर सरकार से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्माण और तोड़-फोड़ (डिमोलिशन) के काम से उड़ने वाली धूल को कैसे रोका जाए,इस



पर भी सभी पक्ष अपनी राय दें। इसके लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कुछ उपाय सुझाए हैं। बेंच ने सभी पक्षों को 12 मार्च से पहले अपनी-अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि

CAQM के सुझावों के आधार पर 12 मार्च को गाड़ियों से होने वाले एयर पॉल्यूशन के मुद्दे की जांच करेगा। कोर्ट ने कहा कि इन नोटिसों को ही आधिकारिक सूचना माना जाएगा। राज्यों को मिले सुझावों के आधार पर आगे का एक्शन प्लान भी कोर्ट में जमा करना होगा। कोर्ट ने पर्यावरण, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा मंत्रालय से कहा कि वे मिलकर एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करें, जिसमें एनसीआर के कोयला आधारित उद्योगों को धीरे-धीरे बंद करने की योजना हो। इस योजना में यह भी बताया जाए कि कौन-कौन से उद्योग प्रभावित होंगे,उन्हें कौन सा वैकल्पिक ईंधन दिया जा सकता है।

दरभंगा जा रही डबल डेकर बस लखनऊ में पलटी,पांच यात्रियों की मौत

लखनऊ,23 फरवरी 2026। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को एकडबल डेकर बस सड़क पर पलटने से पांच यात्रियों की मौत हो गई है। हदसे में करीब 10 से 12 लोग घायल भी हुए हैं। बस बिहार के दरभंगा जा रही थी। घटना की जानकारी पर पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव शुरू किया। पुलिस मृतकों की संख्या की अभी पुष्टि

नहीं है। मृतकों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि डबल डेकर बस यात्रियों को लेकर लुधियाना से दरभंगा जा रही थी।जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के खेमा खेड़ा गांव के पास बस अचानक अनियंत्रित होकरसड़क पर पलट गई। दुर्घटना होते ही सवारियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

एआई समिट हंगामा...5 वां आरोपी एमपी से गिरफ्तार,यूथ कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट से भी पूछताछ,आरोपी कृष्ण हरि की कार से पीएम फेंस वाली टीशर्ट मिली

नई दिल्ली,23 फरवरी 2026। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यूथ कांग्रेस नेता जीतेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 और सदस्यों को हिरासत में लिया है। सोमवार को पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष उदय भानु चिव से भी

सभी शर्टलैस प्रदर्शन में शामिल थे। वीडियो के जरिए इनकी पहचान की गई है। दिल्ली की तिलक नगर थाना ने यह एक्शन लिया है। सभी को दिल्ली लाया गया है। इस मामले में पुलिस गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। 21 फरवरी को पटयाला कोर्ट ने पहले से गिरफ्तार 4 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था। दरअसल, 20 फरवरी को इंडियन यूथ कांग्रेस के 11 सदस्यों

ने भारत मंडपम में घुसकर एआई समिट के दौरान शर्टलैस होकर पीएम मोदी की फोटो वाली टी-शर्ट लॉफ़ीमाड्ड के नारे लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपी और यूथ कांग्रेस के नेता कृष्ण हरि की गाड़ी हंगामा करने के विरोध में भाजपा ने पूरे देश में विरोध किया था।



पूछताछ की है। ग्वालियर से हिरासत में लिए गए दो लोगों ने राजा गुर्जर और अजय कुमार के नाम शामिल हैं। आरोप है कि ये

राष्ट्रपति भवन में राजाजी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति ने कहा...आत्मगौरव का सम्मान

नई दिल्ली,23 फरवरी 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन परिसर में आजाद भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राजाजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समर्पित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी 24 फरवरी से 1 मार्च तक राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में आने वाले आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। अशोक मंडप के समीप ग्रैंड ओपन सीटों पर स्थापित राजाजी की यह प्रतिमा पहले वहां लगी एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर लगाई गई है। इसे औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को समाप्त करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत तथा राष्ट्रीय आत्मगौरव को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई राजाजी की प्रतिमा का अनावरण करना उनके लिए ऐतिहासिक अवसर है। राजाजी को सम्मानित कर देश ने अपने आत्मगौरव का सम्मान किया है। उन्होंने स्मरण कराया कि जब राजाजी गवर्नमेंट हाउस (अब राष्ट्रपति भवन) पहुंचे थे, तब उन्होंने अपने कक्ष में रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी के चित्र लगाए थे। इससे उन्होंने



यह संदेश दिया कि भारत भले ही औपचारिक रूप से डोमिनियन रहा हो, लेकिन भारतीयों के हृदय में स्वराज स्थापित हो चुका था। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विरासत पर गर्व करने और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का जो राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, उसमें राजाजी के आदर्श स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान शासक जनता से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र का मूल सिद्धांत जन-जन से जुड़ाव है। राष्ट्रपति भवन राष्ट्र का भवन है और इसके द्वार सभी देशवासियों के लिए खुले हैं। राष्ट्रपति ने 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर अग्रसर देशवासियों से राजाजी के आदर्शों से प्रेरणा

लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजाजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और विधि,स्वतंत्रता संग्राम,सामाजिक-आर्थिक सुधार,प्राचीन भारतीय ग्रंथों,तमिल एवं अंग्रेजी साहित्य,कविता,संगीत,राजनीति और प्रशासन जैसे अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। इस अवसर पर आयोजित 'राजाजी उत्सव' को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राजाजी की प्रतिमा का अनावरण औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्ति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्रिया एक सतत परिवर्तन है,जो शासन,कानून,शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुलामी मानसिकता से मुक्ति की परिकल्पना को अनेक पहलों के माध्यम से साकार किया गया है। इनमें राजभवनों को लोकभवनों के रूप में विकसित करना,औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों को निरस्त करना,इंडिया गेट के समीप सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना तथा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण शामिल है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आरंभ की गई पहलों-जैसे उद्यानों की अमृत उद्यान के रूप में खोला,दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप करना तथा परम वीर चक्र विजेताओं के चित्र स्थापित करने का भी उल्लेख किया और कहा कि ये कदम भारत के सभ्यतागत आत्मविश्वास को सुदृढ़ करते हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. सस्कुति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शोखावत,राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल,सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन,जलशक्ति राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी,उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री निमेषुन जयंतभाई बंधानिया और राजाजी के परिजनों सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।



शशि थरूर, निशिकांत दुबे,अनुराग ठाकुर,भर्तृहरि महाताब, डॉ. पुरंदेश्वरी, संजय कुमार झा, हेमा मालिनी,बिप्लब कुमार देव, डॉ. सुधांशु त्रिवेदी,जगदीशका पाल, डॉ. सस्मित पात्रा, अपराजिता सारंगी, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, पीवी मिथुन रेड्डी और प्रफुल्ल पटेल को विभिन्न देशों से संबंधित समूहों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन देशों के साथ मैत्री समूह गठित किए गए हैं,उनमें श्रीलंका,जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, भूटान,सऊदी अरब,इजराइल, मालदीव, अमेरिका,रूस, दक्षिण कोरिया,नेपाल,यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, इटली, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस,सिंगापुर, ब्राजील, वियतनाम, मेक्सिको, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इसके अतिरिक्त

यूरोपीय संसद के साथ भी संसदीय संवाद को संस्थागत रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सांसदों को अपने विदेशी समकक्षों से सीधे संवाद का अवसर प्रदान करना है। इन समूहों के माध्यम से व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक नीतियों और वैश्विक चुनौतियों जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा। नियमित बैठकें, अध्ययन दौरे और संयुक्त कार्यक्रमों के जरिए दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बिरला ने कहा कि संसदीय कूटनीति भारत की वैश्विक पहचान को सशक्त बनाती है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की भूमिका को और प्रभावी बनाती है।

संपादकीय



जाति विभाजन की गहरी होती दरारें

उच्च शिक्षा परिसरों में समता लाने के नाम पर विन्धविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल में जारी दिशा-निर्देशों ने न केवल जाति विमर्श को चर्चा के केंद्र में ला दिया है,बल्कि हिंदू समाज एक बार फिर जातीय खांवों में बंटता नजर आ रहा है। आर्थिक और शैक्षिक विकास के कारण जाति विभाजन की जो रेखाएं समय के साथ धुंधली पने लगी थीं,वे अब पुनः गहरी होती दिखाई दे रही हैं...

वर्तमान परिस्थितियां मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद उत्पन्न हुए उस दौर की याद दिला रही हैं, जब हिंदू समाज स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया था। आज समाज फिर उसी राह पर अग्रसर दिख रहा है। जाति के आधार पर राजनीतिक गतिधाराएं संकेन वाले कुछ दल छात्रों के बीच इस विमर्श को हवा दे रहे हैं,ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। इसके विपरीत,सर्वग्न समाज भी अपने हितों की रक्षा के लिए छात्रों को लामबंद करने में पूरी शक्ति से जुटा हुआ है। यदि यूजीसी के इन दिशा-निर्देशों का कोई सर्वसमावेशी और सर्वमान्य हल नहीं खोजा गया, तो इसका सीधा असर भविष्य की राजनीति पर पड़ेगा। इससे न केवल सामाजिक समरसता प्रभावित होगी, बल्कि व्यापक हिंदू एकता का लक्ष्य भी संकट में पड़ सकता है।

जहां सामाजिक,शैक्षिक और आर्थिक विकास ने जातिगत विभाजन की दीवारों को कमजोर किया,वहीं राजनीति इसे पुनः उभारने में सफल रही है। पिछड़ी जातियों के उत्थान के नाम पर जाति विमर्श को सत्ता के केंद्र में लाने का मुख्य श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाता है। उन्होंने 1990 में चौधरी देवीलाल के राजनीतिक रसूख को काबू में करने के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। उस निर्णय ने हिंदू समाज को वैचारिक और सामाजिक स्तर पर बुरी तरह विभाजित कर दिया।

तब मंडल आयोग के विरोध में लगभग समूचा उत्तर भारत सुलगा उठा था और सर्वग्न समुदाय के युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय प्रतीत होने लगा था। मंडल आयोग द्वारा पैदा की गई इस सामाजिक खाई को बाद की राजनीति ने पाटने के बजाय और अधिक गहरा ही किया है। जब समाज ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण को धीरे-धीरे स्वीकार करना शुरू किया,तभी वर्ष 2006 में मनमोहन सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रविधान कर दिया।

इस निर्णय के विरोध में छत्र एक बार फिर सड़कों पर उतर आए,जिससे सामाजिक विभाजन की दरारें और चौड़ी हो गईं। आज जब देश इन पुराने संघर्षों की स्मृतियों से उबर ही रहा था,तभी यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों ने भारतीय समाज को पुनः एक गहरे अंतर्द्वंद्व और सामाजिक संघर्ष के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। यद्यपि यह संघर्ष अभी सार्वजनिक रूप से सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विश्वविद्यालयों के परिसर इस वैचारिक उबाल की चपेट में हैं। वर्तमान में शैक्षणिक परिसर दो स्पष्ट गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं-एक तरफ इस गाइडलाइन के प्रबल समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ इसके तीखे विरोधी।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून, 1961 को सभी मुख्यमंत्रियों के नाम एक विस्तृत पत्र लिखा था। इस पत्र में नेहरू जी ने वर्तमान जाति-आधारित आरक्षण की व्यवस्था को एक प्रकार से नकार दिया था। वे आरक्षण-आधारित विकास के स्थान पर एक ज्ञान-केन्द्रित समाज का निर्माण करना चाहते थे। नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था...मुझे किसी भी रूप में आरक्षण पसंद नहीं है,विशेषकर नौकरियों में आरक्षण। मैं ऐसे किसी भी कदम के विरुद्ध हूं जो अक्षमता को बढ़ावा देता है और हमें औसत दर्जे की ओर ले जाता है।

नेहरू का मानना था कि यदि हमें देश को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना है,तो हमें योग्यता को प्राथमिकता देनी होगी। विडंबना यह है कि यदि यूजीसी की वर्तमान गाइडलाइन का विरोध करने वाले लोग आज पंडित नेहरू के इन शब्दों को दोहराएं,तो उन्हें तुरंत सामाजिक न्याय का विरोधी करार दे दिया जाएगा। यह तथ्य दर्शाता है कि पिछले छह दशकों में भारतीय राजनीति और सामाजिक विमर्श की दिशा कितनी बदल चुकी है।

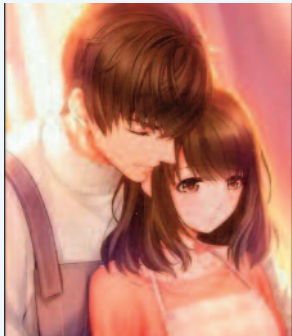
मंडल आयोग के लागू होने के बाद देश में जो राजनीतिक विमर्श स्थापित हुआ, उसमें सर्वग्न समाज प्राप्ति विरोधी कहलाने के भय से एक लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। किंतु बाद के वर्षों में विशेषकर एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग और आरक्षण के निरंतर विस्तार ने इस वर्ग के भीतर एक दबाव पैदा किया। राम मंदिर आंदोलन के पश्चात सर्वग्न समाज ने जिस तरह एकतरफा भाजपा का दामन थामा था, वह अब इस नई गाइडलाइन से भीचक्का रह गया है। यही दबाव और विस्मय अब गुप्से में परिवर्तित हो रहा है। सत्ता की बात जोह रहे विपक्षी दल पदों के पीछे से इस असंतोष को हवा तो दे रहे हैं, किंतु वे खुलकर बोलने से बच रहे हैं।

उन्हें भय है कि सवर्णों का पक्ष लेने पर कहीं उनका पिछड़ा वोट बैंक न बिटक जाए। भाजपा सरकार और संघटन के शीर्ष नेता इस जातीय विमर्श को ठंडा करने के प्रयासों में जुटे हैं,लेकिन इस समस्या का समाधान खोजने में जितनी विलंब होगी,जाति विमर्श उतना ही प्रखर होता जाएगा। यदि समय रहते सर्वग्न समुदाय का यह गुस्सा शांत नहीं हुआ,तो आने वाले चुनावों में भाजपा के लिए नई और कठिन चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

सच्ची मोहब्बत...



मुस्कान केशरी
मुजफ्फरपुर,बिहार



देखो ऐसा नहीं है की सच्ची मोहब्बत है नहीं,आज भी कई ऐसे उदाहरण है जो सच्ची मोहब्बत को दर्शाती है। जिसे पढ़ कर लगता है, सच में मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है लेकिन कहते हैं ना कि एक सिक्रे के दो पहलू होते हैं जहां सच्ची मोहब्बत है वहां पर झूट- फरेब भी है और इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि जिस हिसाब से यह आधुनिक दुनिया चल रही है इस दुनिया में सच्चा प्यार मिलना इतना आसान है। आजकल प्यार में व्यापार होने लगा है और व्यापार में प्यार होने लगा है। प्यार, मोहब्बत,इश्क़ निस्वार्थ होता है यह बात कहां कहां समझ पाता है हर कोई आजकल प्यार में बस फायदा ही फायदा खोजता है और कोई शकल तो कोई पैसा देखाता है कोई रुतबा तो कोई ताकत देखाता है और सच्चे दिल की पक्वाह कहां है किसी को और सच ये भी है कि आजकल सच्चा इंसान कहां कहां खोजना चाहता है। लड़कियों को फेने में रिचार्ज करवाने वाला चाहिए और लड़कों को उनकी चाहतें पूरी करने वाली लड़कियां चाहिए। एक लड़का और एक लड़की अपनी जरूरत के अनुसार प्यार अब खोजने लगा है,कब कहां एक झलक वाला प्यार होता है। जिसे लोग आज-कल प्यार कहते है वो प्यार नहीं, व्यापार है यह बात लोग समझते ही नहीं

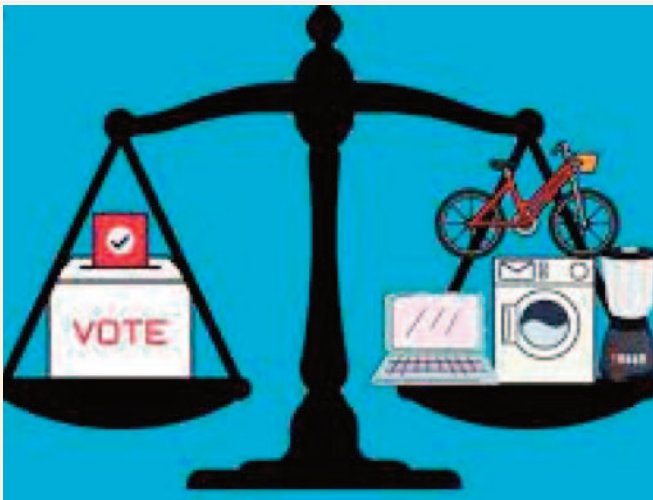
है। मैंने तो देखा है मोहब्बत में तड़पते हुए,मरते हुए और बड़ी शिद्दत से बेवफा होते हुए लोगों को और जो कहते थे कि हम तुम्हरी मोहब्बत में मर जायेंगे लेकिन किसी दूसरे के नहीं होंगे। आज वही मंडप पर खड़े होकर हंसते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं और दूसरे के साथ अपने जीवन के आगे के सफर को तय कर रहे हैं। जो कहते थे हम तुम्हारे साथ इस जन्म क्या सातों जन्म साथ रहकर दिखलाएंगे। वो आज कहते हैं कि तुम्हारे साथ एक पल रहना मुझे मुश्किल सा लगता है। जो कहते थे तुम बिन मेरा मन नहीं लगता है आज वो कई सालों से बात नहीं कर रहे हैं और सामने अगर दिख जाए तो वो ऐसे नजर घूमते हैं जैसे वो मुझे जानते ही नहीं। जब उसे कौन बताएं कि उसकी याद में मैंने ना जाने कितने तकिए भोगाए है। इसलिए मोहब्बत की कोई परिभाषा होती नहीं है मोहब्बत में एहसास होता है जो निस्वार्थ होता है और जहां पर आपको लगे कि वो निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ भवनाएं बन चुकी हैं उस रिश्ते से आप मुक्त हो जाएं और जो जाना चाहते जिंदगी से, उसे खुशी - खुशी विदा कर दे क्योंकि मोहब्बत स्वतंत्रता देता है, मोहब्बत कभी कैद नहीं करता किसी को। मोहब्बत में विश्वास करना होता है किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है और उसी खूबसूरत एहसास के साथ हर किसी को जीना चाहिए।।



ललित गर्ग
पटपटगंज,दिल्ली-92

भारतीय लोकतंत्र की विडंबना यह है कि चुनाव आते ही जनसेवा का स्वरूप बदलकर जनलुभावन राजनीति में परिवर्तित हो जाता है। राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं को चुनावी सफलता का शॉर्टकट बना लिया है। मतदाताओं को तात्कालिक आर्थिक लाभ देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति लगातार मजबूत हो रही है। आगामी तीन-चार माह में विधानसभा चुनाव होने हैं,इसी संदर्भ में जब असम, पश्चिम बंगाल,केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक सरगमियां तेज हुईं,तब इस संस्कृति का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी प्रभूमि में देश की शीर्ष अवलत, सर्वोच्च न्यायालय, ने मुफ्त की योजनाओं के अनियंत्रित विस्तार पर गंभीर टिप्पणी की। यह टिप्पणी केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को लेकर एक चेतावनी है।

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरिब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुस्थला योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरिक्त उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को



तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं। जब राजस्व घाटे से जुझ रहे राज्य मुफ्त बिजली,मुफ्त यात्रा या नकद वितरण की घोषणाएं करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि यह संसाधन कहां से आएंगे और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? राजकोषीय अनुशासन किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत का आधार है। यदि राज्य अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए खजाने को खाली करता है, तो दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। जो धन बुनियादी ढांचे के निर्माण, अस्पतालों के सुदृढीकरण, विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार और रोजगार सृजन में लगना चाहिए,वह वोटों की फसल काटने में खर्च हो जाता है। यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं,बल्कि नैतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। लोकतंत्र में मतदाता की स्वतंत्रता सर्वोपरि मानी जाती है। यदि मतदाता को परोक्ष रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर प्रभावित किया जाता है, तो यह स्वतंत्र निर्णय की भावना को कमजोर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने तार्किक प्रश्न उठाया कि राज्य रोजगार सृजन और कौशल विकास पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देते? वास्तव में रोजगार ही स्थायी सशक्तीकरण का माध्यम है। जब व्यक्ति अपने श्रम और कौशल से आय अर्जित करता है, तब उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं। इसके विपरीत,निरंतर मुफ्त सुविधाएं व्यक्ति को निर्भर बनाती हैं। धीरे-धीरे

परिश्रम की संस्कृति कमजोर पे ती है और समाज में अकर्मण्यता की मानसिकता पनपने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र की सुदृढता के लिए खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं,बल्कि सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकता का नाम है। चुनाव पूर्व घोषित योजनाओं की निष्पक्षता भी प्रश्नों के घेरे में है। जब आचार संहिता लागू रहने के दौरान बड़े पैमाने पर आर्थिक वितरण होता है, तो विपक्षी दल इसे असमान प्रतिस्पर्धा मानते हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष निगरानी की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग पर आती है। निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी दल मतदाताओं को अप्रत्यक्ष रिश्त देकर चुनावी लाभ न ले। आचार संहिता का उल्लंघन केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन है। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में यह प्रवृत्ति और गहरी जड़ें जमा सकती है। निःस्पंदेह,इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राज्यों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की खास तौर से देखभाल करें। हालांकि, जब राजस्व घाटे वाले राज्य मुफ्त की योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, तो सरकारी खजाने पर दबाव और अधिक वे जाता है। विडंबना यह है कि जिस धनराशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे में सुधार,स्वास्थ्य सेवाओं का मार्ग है, वह सक्षम बनाने और शिक्षा की सुविधा को

समृद्ध करने के लिये किया जाना चाहिए,वो राशि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये खर्च कर दी जाती है। जरूरत इस बात की है कि कौशल विकास के जरिये लोगों को इस तरह सक्षम बनाया जाए जिससे उन्हें दीर्घकालिक व स्थायी लाभ मिल सकें। यह भी समझना होगा कि मुफ्त योजनाओं का हर स्वरूप गलत नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत देना, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय सहायता पहुंचाना,सामाजिक न्याय के तहत वंचित वर्गों को अवसर देना-ये सब राज्य की जिम्मेदारी है। परंतु चुनावी मौसम में अचानक घोषणाओं की बाढ़ आ जाना और दीर्घकालिक वित्तीय परिणामों की अनदेखी करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत नहीं है। यह राजनीतिक दलों के वैचारिक दिवालियेपन को दर्शाता है, जहां दूरदृष्टि की जगह तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र की मजबूती केवल संस्थाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों की सजगता से भी आती है। यदि मतदाता केवल तात्कालिक लाभ देखकर मतदान करता है, तो वह अनजाने में ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करता है जो अंततः उसी के भविष्य को प्रभावित करती है। परिपक्व मतदाता वहीं है जो घोषणाओं के पीछे की मंशा और आर्थिक व्यवहार्यता को समझे। वह यह पछे कि पांच साल बाद राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, विकास की दिशा क्या होगी और रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे। लोकतंत्र में वोट केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है।

आज भारत स्वयं को वैश्विक मंच पर एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। हम विश्वगुरु बनने का संकल्प लेते हैं,लेकिन यदि हमारी राजनीति लोकलुभावनवाद के जाल में उलझी रहेगी,तो यह संकल्प खोखला सिद्ध होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव तभी सार्थक है जब हमारी नीतियां दूरदर्शी, संतुलित और टिकाऊ हों। मुफ्त की संस्कृति से बाहर निकलकर उत्पादकता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। यह समय आत्मसंभन का है। राजनीतिक

दलों को समझना होगा कि जनता को सशक्त बनाना केवल धन बांटने से संभव नहीं है। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार-ये चार स्तंभ किसी भी राष्ट्र की मजबूती तय करते हैं। यदि इन पर निवेश बढ़ेगा,तो नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और राज्य पर बोझ कम होगा। वहीं,नागरिकों को भी यह ठानना होगा कि वे तात्कालिक प्रलोभनों के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देंगे। लोकतंत्र की सुदृढता तभी सुनिश्चित होगी जब शासन और जनता दोनों अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।

निःस्पंदेह,चुनावी निष्पक्षता के लिये यह आवश्यक हो गया है कि चुनाव से पहले घोषित की गई या लागू की गई लोकलुभावनी नीतियों व योजनाओं की गहन पे ताल की जाए। विपक्षी दलों द्वारा बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया था कि पिछले साल अक्तूबर में आचार संहिता लागू रहने के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 15,600 करोड़ रुपये दिए गए थे। जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध कदम था। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपरोक्ष रूप से रिश्त देने के प्रयासों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही इस दिशा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में कार्रवाई भी करनी चाहिए। निर्विवाद रूप से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पक्षतापूर्ण रवैया अपनाना हमारे जीवंत लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। यह कार्य करने की मानसिकता को बाधित करती है और समाज में सरकार-निर्भरता एवं अकर्मण्यता की संस्कृति को जन्म देती है। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया गया,तो आर्थिक असंतुलन और राजनीतिक अविश्वास दोनों बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि नीतियों की पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और चुनावी निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यही लोकतंत्र की वास्तविक रक्षा है,यही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।

अच्छे कर्म करो प्रेम से करो,भगवान राम साथ देंगे



अण्णुशक्तिनगर,मुंबई

प्रेम का कोई अन्त नहीं है इसलिए मनुष्य को कभी ना तो किसी से डरना चाहिए और ना ही तनाव लेना चाहिए। प्रेम सही में आपको अपना यश दिला सकता है आपको सच और गलत का बोध करा सकता है अगर किसी के दिल में आपके प्रति सच्चा प्यार नहीं है तो वहीं से हटे नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। सेक्स में प्रेम होता भी है और नहीं भी इसी में आप धोखा खाते हैं। आप जहाँ चले यदि जोर जबरदस्ती करते हैं तो वो ठीक नहीं है। समय हमेशा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है यदि आपको लगता है कि ये प्रेम झूठा है तो और कहीं गलत जगह ना

जाएँ क्योंकि अगर कीचड़ में पैर फँसता है तो वहीं आसपास सब कीचड़ ही रहते हैं। भागदौड़ ना कर शांति से काम लें। कीचड़ कुछ देर के बाद सूर्य के ताप से मिट्टी होगा या तो गल जाएगा और फिर जो रास्ता आगे का होगा वो सुगम होगा और आप वहीं से बचेंगे भी और फिर दोबारा वहाँ जायेंगे भी नहीं इसके लिए मन को नियंत्रण करना होगा। हड़बड़ में भय होता गड़बड़ होती है और आदमी अपना इम्युनिटी सिस्टम खो देता है जो उसके जीवन का रक्षक है। इसलिए भगवान राम का ध्यान करना आज के कलयुगी रिश्ते में अति आवश्यक है क्योंकि आप तो किसी के भलाई के लिए करते हैं बाद में वहीं धोखा खाते हैं क्योंकि आज भलाई करना है तो गरीबों को दान कर दो लेकिन रिश्तेदारी में यदि एक दो बार धोखा लगे तो समझ लेना कोई आपकी मजबूरी का गलत फायदा उठा रहा है। भगवान राम नहीं है। समय हमेशा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है यदि आपको लगता है कि ये प्रेम झूठा है तो और कहीं गलत जगह ना



इसलिए यहाँ भगवान राम खुद ही आपको बचाने आ जाते हैं क्योंकि कभी वो अपने भक्तो को कष्ट में नहीं रहने देते हैं उसके लिए आपको इन्द्रियों को संयम करना चाहिए नहीं तो आप डॉ के पास जा जाकर पुरी जिंदगी पीड़ित अवस्था में ही निकाल देते हैं। आनन्द कहीं मिला लोग कहते हैं सेक्स में बड़ा आनंद आता है । इसलिए खुब डांस करो लेकिन ये आनंद

नहीं बल्कि मौत के करीब जाना है क्योंकि गलत संगत और मन का मचलना किसी अन्य के साथ गलत करा सकता है और आप कोई जुर्म कर बैठते हैं आज लोग डांस गाना होली में गाली गलौज क्यों करते हैं क्योंकि वो मदिरा का सेवन कर ही इसान को हैवान समझ लेते हैं और गन्दी-गन्दी गाली और महिलाओ को देख कर नंगा नाच कर अपने चरित्र को ही

अपवित्र करते हैं। जब भी काम का वेग आता है तो उसके साथ क्रोध भी आ जाता है और उसे संभाले कौन। जो जाएगा वो पीट जाएगा और बाद में वही जुर्म का रूप लें लेता है और उस समय होश खो देता है लेकिन जब ये बात समाज में फैलती है तो लोग पीट-पीट कर उसे अधमरा भी कर देते हैं क्योंकि आपको एक समाज में रहना है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः आप में और जानवर में यही अंतर है कि उसका समाज किसी से बंधा नहीं है लेकिन आप एक सीमा के अंदर होते हैं जहाँ समझकर चलना पड़ता है और नारी का सम्मान करना समाज की ही नहीं देश की शान है। इसलिए हमें हमेशा गलत होने पर इधर-उधर भटकना नहीं है बल्कि खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और माता पिता का सम्मान करना चाहिए। एक बार दृष्टि मिली राम और सीता जी की, प्रेम के लिए ही राम धनुष उठाते हैं । राम नहीं चाहते थे सीता साथ जाएं वन,सीता जी की हट पर वन

संग लाते लेकिन माता सीता को राम से अपार प्रेम था जो उसे साथ में लेकर आई इसी तरह भगवान लखन का अपने बड़े भाई राम से प्रेम जो भाई भाई में अपार प्रेम का प्रतिक है क्योंकि भगवान राम ही सच्चा प्रेम है जहाँ ना तो कोई रोक-टोक है ना ही किसी से बैर सबको के साथ में लेकर चलना और उनके दुःखो में सदैव साथ रहना ही सच्ची भक्ती है। भगवान राम के जीवन अहम हिस्सा थीं और उनके साथ राम ने अनेक समय बिताए। राम की वाणी से सीता के आचरण तक,सभी चीजें उन्हीं सीता में प्यार करने के लिए प्रेरित करती थीं। राम ने सीता के लिए लंका जाकर उन्हें बचाया था और उनका प्यार अज्ञातवास के समय भी कम नहीं हुआ था। इसलिए, सीता ही भगवान राम के जीवन में सबसे अधिक प्रिय होती थीं।बाद में भगवान राम और हनुमान का प्रेम भी इतिहास में आज भी अमर है।

बांग्लादेशी और पाकिस्तानी

आतंकी संगठनों के बीच साठगांठ

-स्वराज श्रीवास्तव-

दिल्ली पुलिस की ओर से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए आठ सदिंध आतंकवादियों के बारे में जिस तरह यह जानकारी सामने आई कि वे देश की राजधानी में किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे,उससे यही पता चलता है कि आतंकी संगठनों का दुस्साहस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु और बंगाल से जो आतंकी गिरफ्तार किए गए,उनमें से अधिकांश बांग्लादेशी हैं,लेकिन वे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के इशारे पर काम कर रहे थे। उनका हैडक्वार्टर बांग्लादेश में बैठा एक कुख्यात कश्मीरी आतंकी बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के बीच साठगांठ कायम हो गई है। यह एक नया खतरा है और इससे भारत की चिंता बढ़ जाना स्वाभाविक है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि पाकिस्तान और



बांग्लादेश के आतंकी तत्वों के बीच साठगांठ पिछले लगभग डेढ़ वर्ष में तब हुई, जब मोहम्मद यूनूस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का संचालन कर रहे थे। यह किसी से छिपा नहीं कि इस दौरान उन्होंने न केवल अपने देश के भारत विरोधी कट्टरपंथी तत्वों को उकसाने का काम किया,बल्कि पाकिस्तान से संबंध बढ़ाने में भी जुटे रहे। हैरानी नहीं कि इस सबके चलते पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के सरगना बांग्लादेश पहुंचे

होंगे। जो भी हो,भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि कश्मीर के बहाने आतंकी तत्वों को बहकाने और उकसाने का काम जारी है। दिल्ली पुलिस की ओर से पकड़े गए आतंकियों के दुस्साहस का पता इससे चलता है कि उन्होंने दिल्ली और कोलकाता में भारत विरोधी पोस्टर चस्पा किए थे। इन पोस्टरों की छानबीन के तहत ही दिल्ली पुलिस सदिंध आतंकियों तक पहुंची। ध्यान

रहे कि कुछ महीने पहले दिल्ली में लालकिले के निकट धमाका करने वाले आतंकी के साथियों ने भी इसी तरह श्रीनगर में भारत के खिलाफ पोस्टर लगाए थे। श्रीनगर में लगाए गए पोस्टरों की छानबीन से ही फरीदाबाद के उस आतंकी माइयूल का भंडाफेड़ हुआ था, जिसमें कई डाक्टर शामिल थे और जिनमें से एक ने आत्मघाती हमलावर बनकर लालकिले के निकट कार में विस्फोट किया था। ये दोनों घटनाएं यही बताती हैं कि पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों को प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी गहन जांच भी करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के हथ आए सदिंध आतंकियों के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं और वे उन्हीं के जरिये तमिलनाडु एवं कोलकाता में काम कर रहे थे। इसका अर्थ है कि लोगों को इसके लिए अगाह किया जाए कि वे किसी को काम पर रखने के पहले उनके पहचान पत्रों की जांच सावधानी से करें।

कछार बखरी,हरियर लागय



अशोक पटेल आशु
शिवरीनारायण छत्तीसगढ़

भदके है चना उन्हारी मुंगेर मेड़-पार तील राहेर हर दमके अउ दमके मुंग,क्यारी केशर। मस्त-मगन,माते है रुखवाई धरसा लाली-लाली ललियाए सुम्हर फुलगे,अमली हर फरगे दुमर-गरती घलो, हर गदराए। तेंदु चार मकोईया हर फरगे बर-पीपर, पीकरी लटलटाए लट-लट ले,लाली बोईर पाके बारी-बखरी,गमके गमकाए। सरई-साजा-सैगोना है डोंगरी बांस-भीरहा,हर कट-कटाए मझा कुचियाए, फुल टपके मन-मझा के निशा छा जाए। मोच-महीना हर,आगे रे सगी मेला-मड़ाई हर,सुपख गंगो संगी-जहूरिया के फट्टो नरियर बिहा-पटौनी के लगन धरागे।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक



मोमिनपुरा में 100 से अधिक संदिग्धों के सैपल दूषित पानी पर गहराया सवाल

पानी के नमूने जांच के लिए भेजे

नगर निगम आयुक्त डी.एन. कश्यप ने बताया कि दूषित जल आपूर्ति की शिकायत मिलते ही जांच टीम गठित कर दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों से पानी के कई नमूने लेकर जांच के लिए रायपुर भेजे गए हैं। रिपोर्ट मिलते ही आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उबला पानी पीने की सलाह

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से उबला हुआ पानी पीने, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने और लक्षण दिखाई देने पर तत्काल जांच कराने की अपील की है। अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं कि संक्रमण की असली वजह क्या सामने आती है और प्रशासन कितनी तेजी से प्रभावी कदम उठाता है।



पाइप लाइन मरम्मत जारी, सफाई पर सवाल

नगर निगम की जल शाखा क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की मरम्मत में जुटी है। हालांकि प्रभावित इलाकों में नियमित सफाई और क्लोरीनेशन की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल आपूर्ति की गुणवत्ता की निगरानी सख्तो से नहीं हो रही।

केवल एक पाइप लाइन की खराबी नहीं...

नेता प्रतिपक्ष शशी अहमद ने निगम आयुक्त पार्श्वों, स्वास्थ्य विभाग और जल शाखा के कर्मचारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यदि यह केवल एक पाइप लाइन की खराबी का मामला होता, तो संक्रमण सीमित क्षेत्र तक रहता। अलग-अलग बस्तियों में मरीज मिलना व्यापक स्तर पर लापरवाही की ओर इशारा करता है। उन्होंने आशंका जताई कि कई स्थानों पर पाइप लाइन मरम्मत कार्य मानक के अनुरूप नहीं हुआ है या फिर जल शुद्धिकरण संयंत्र में एलम, ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का उपयोग निर्धारित मात्रा में नहीं किया जा रहा। यदि पानी का समुचित शुद्धिकरण नहीं हो रहा, तो दूषित पेयजल इस प्रकोप की जड़ हो सकता है।

प्रेम प्रसंग में युवक ने कीटनाशक पीया, इलाज के दौरान मौत

ग्राम कुल्हाड़ी का मामला, पुलिस कर रही जांच

-संवाददाता-

अंबिकापुर, 23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर में एक 20 वर्षीय युवक ने कथित रूप से प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद कीटनाशक का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गणेश कुमार (20) पिता बुधराम, निवासी ग्राम कुल्हाड़ी, थाना गांधीनगर क्षेत्र का रहने वाला था। परिजनों ने बताया कि 15 फरवरी की शाम करीब 6 बजे वह मजदूरी कर घर लौटा था। भोजन के लिए पुछने पर उसने बाद में खाने की बात कही और कुछ देर बाद फिर बाहर चला गया। करीब डेढ़ घंटे बाद लौटने पर उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। रात में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और खून की उल्टी होने लगी। पुछने पर उसने कीटनाशक पीने की बात स्वीकार की। परिजन उसे तत्काल मिशन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां एसआईसीयू वार्ड में उसका उपचार चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल में युवक ने परिजन को बताया था कि कल्याणपुर क्षेत्र की एक युवती से उसके प्रेम संबंध थे और मनमुटाव के कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रुपए व मोबाइल लूट का फरार आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-

अंबिकापुर, 23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

रुपए व मोबाइल लूट के मामले में फरार आरोपी को दरिमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बुचन राम नांगेसिया मोहनपुर पटेलपारा थाना दरिमा का रहने वाला है। 30 दिसंबर को वह ससुराल पहाड़पारा से पैदल घर जा रहा था। झोले में दस हजार रुपए व एक मोबाइल था। रास्ते में बाइक सवार तीन युवकों ने लूटकर फरार हो गए थे। बुचन की रिपोर्ट पर दरिमा पुलिस ने पूर्व में दो आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी। जबकि मनीष उर्फ पतों उर्फ लक्ष्मण यादव पिता चक्रधारी यादव उम्र 21 वर्ष निवासी वन्दना यादवपारा थाना सीतापुर फरार चल रहा था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।



कोयला चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-

अंबिकापुर, 23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

लखनपुर स्थित अमेरा कोल खदान से कोयला चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी संगठित गिरोह बनाकर कोयला चोरी करता था। पुलिस ने आरोपी के घर से चोरी के 2.5 टन कोयला व घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार लखनपुर स्थित अमेरा कोल खदान से कोयला चोरी की शिकायत लगातार पुलिस को मिल रही थी। डीआईजी राजेश अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश लखनपुर पुलिस को दिए थे।



पुलिस ने आरोपी आनंद राम केवट पिता सुखराम केवट उम्र 36 वर्ष पुहपुरापारा थाना लखनपुर को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह बनाकर कोयला चोरी करता था। पुलिस ने इसके घर के आंगन से

चोरी की कोयला 2.5 टन व घटना में युक्त बाइक भी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुडबॉल में आकाश और रजत को बड़ी जिम्मेदारी

-संवाददाता-

अंबिकापुर, 23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में सरगुजा जिले के दो राष्ट्रीय खिलाड़ियों को रेफरी बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। यह प्रतियोगिता मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल में 23 से 27 फरवरी तक आयोजित हो रही है। वुडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरगुजा के आकाश दुबे और रजत सिंह को निर्णायक मंडल में शामिल किया है। राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि सरगुजा के खिलाड़ी अब केवल खेल प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि तकनीकी और संचालन स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। आकाश दुबे और रजत सिंह पूर्व में भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सफलतापूर्वक निर्णायक की भूमिका निभा चुके हैं। इस चैंपियनशिप में देशभर की लगभग 65 विश्वविद्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऐसे प्रतिष्ठित आयोजन में सरगुजा के खिलाड़ियों की रेफरी बोर्ड में नियुक्ति जिले के लिए गौरव की बात है। रजत सिंह वर्तमान में के.आर. टेक्निकल कॉलेज में क्रीड़ा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। सरगुजा जिला वुडबॉल संघ, जिला बास्केटबॉल परिवार और कॉलेज परिवार ने दोनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।



देशी कट्टा के साथ एक नाबालिग सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-

अंबिकापुर, 23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

देशी कट्टा व कारतूस बेचने के फिराक में घूम रहे स्कूटी सवार एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। जानकारी के अनुसार 22 फरवरी को कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली की केनापारा स्थित एक मेन्स पार्कर के पास तीन



लड़कें देशी कट्टा व कारतूस बेचने के फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्कूटी सवार एक नाबालिग सहित आरोपी पितृपुत्र दुबे पिता मनीष दुबे उम्र 18 वर्ष निवासी बौरीपारा व आकाश

दास पिता स्व. सहेन्द्र दास उम्र 19 वर्ष निवासी केनाबांध बंगाली चौक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 नाग देशी कट्टा व 1 जिनदा कारतूस जब्त किया है। दोनों आरोपी देशी कट्टा व जिनदा कारतूस बेचने के फिराक में थे। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

लरंगसाय चौक से राजपुरी खुर्द तक 6.38 किमी सड़क का होगा चौड़ीकरण

-संवाददाता-

अंबिकापुर, 23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर शहर में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक फोरलेन सड़क की मार्किंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब लरंगसाय चौक से रामानुजगंज मार्ग स्थित राजपुरी खुर्द तक 6.38 किमी सड़क के फोरलेन चौड़ीकरण को प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। इस कार्य के लिए 69.09 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की पहल पर यह स्वीकृति जारी हुई है। मंत्री ने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार जताया है। मंत्री ने कहा



कि फोरलेन निर्माण से नागरिकों को आवागमन यातायात का माध्यम नहीं, बल्कि क्षेत्रीय में बढ़ी राहत मिलेगी। यह सड़क केवल विकास की धुरी बनेगी। व्यापार, शिक्षा और

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और अधिक सुगम होगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क भी मजबूत होगा। रामानुजगंज रोड की स्थिति लंबे समय से खराब बनी हुई है। बारिश के दिनों में कीचड़ और गड्ढों के कारण आवागमन मुश्किल हो जाता है, वहीं सूखे मौसम में उड़ती धूल से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। फोरलेन निर्माण से इन समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने संबंधित विभाग को शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा किया जा सके। मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि रायगढ़ रोड एनएच के उन्नयन की तैयारी भी चल रही है। जल्द ही इस सड़क के लिए भी स्वीकृति मिलने की संभावना है। इससे शहर के चारों ओर सुगम और बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित होगा।

कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, कलेक्टर-एसपी ने ली संयुक्त समीक्षा बैठक

शांति भंग करने वाले गतिविधियों पर प्रशासन की रहेगी कड़ी नजर

-संवाददाता-

बलरामपुर, 23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर राजेन्द्र कटारा एवं पुलिस अधीक्षक वैभव बैकर ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभागार में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में आगामी त्रैमासिक, सीमावर्ती चेकपोस्टों की निगरानी, अवैध गतिविधियों की रोकथाम तथा विभागीय समन्वय को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई।

कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा राजस्व एवं पुलिस विभाग को आपसी



समन्वय और सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को आगामी त्रैमासिक को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारियां समयपूर्व पूर्ण करने,

संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने तथा लोक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिले की सीमाओं पर स्थापित चेकपोस्टों में सख्त निगरानी रखने, बाहनों की

नियमित जांच करने तथा खनिजों के अवैध परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही की अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सतत अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी से

कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने को कहा। पुलिस अधीक्षक वैभव बैकर ने बैठक में कहा कि जिले की कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी असामाजिक गतिविधि पर सतत निगरानी बनाए रखे। उन्होंने सभी को समन्वय के साथ सजगता और सतर्कता से कार्य करने को कहा। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में अन्य विषयों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में वनमण्डलाधिकारी आलोक बाजपेयी, जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर आर.एस. लाल, अभिषेक गुप्ता सहित राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पिता का हत्यारा गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

-संवाददाता-

शंकरगढ़, 23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक कलरूगी पुत्र ने अपने सगे पिता हत्या कर दी पुलिस ने आरोपी हत्यारा पुत्र को गिरफ्तार कर अप. क. 29/2026 धारा - 103(1) बीएनएस कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमांड पर। प्रार्थी सकल राम चेरवा पिता करमा राम जाति चेरवा उम्र 25 वर्ष साकिन कोठली (लेआटोली) थाना शंकरगढ़ जिला बलरामपुर द्वारा दिनांक 22.02.2022 को थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 21.02.2026 के रात्रि करीब 8 बजे यह अपने घर में बैठा था तभी चचेरा भाई बीरकवर चेरवा इसके घर आया और दरवाजा खोलवाया, तब यह दरवाजा खोलकर



बाहर निकला तो इसे बीरकवर बोला कि मेरी पत्नी आपके घर आई है, तब यह बोला कि मेरे घर नहीं आई हैं तो बीरकवर बोला कि मैं अपने पिता को मार कर खत्म कर दिया हूँ तब यह बीरकवर के घर जाकर देखा तो बीरकवर के पिता घर के ढाबा में खून से लथपथ पड़ा हुआ था जिसके सिर, दाहिना कान में, दाहिना घुटना के पास चोट लगा था जो बेहोश पड़ा

था जिसे ईलाज के लिये शंकरगढ़ अस्पताल लेकर गये जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी बीरकवर की पत्नी गोपी बतायी कि बीरकवर अपनी पत्नी गोपी के चरित्र पर शंका करते हुये दिनांक 21.02.2026 के शाम को पत्नी के साथ मारपीट किया था जो अपने बच्चे को लेकर घर से बस्ती तरफ चली गयी थी उसी दौरान शाम करीब 19:45 बजे बीरकवर घर आया और अपनी पत्नी के घर में नहीं होने से अपने पिता हवल चेरवा से पछताछ किया जो तुम्ही मेरी पत्नी को छिपा रहे हो बोलकर लकड़ी के गेड़ा से मारपीट किया है जिससे हवल चेरवा के सिर, दाहिना कान, के पास गंभीर चोट लगने से मृत्यु हुआ है। पुलिस ने प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना शंकरगढ़ में उपरोक्त सदर धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

अंबिकापुर प्लेस ऑफ सेफ्टी कांड: 15 अपचारी किशोर फरार

8 की वापसी...7 अब भी लापता—सुरक्षा,क्षमता और जवाबदेही पर बड़े सवाल

15 अपचारी किशोर फरार: प्लेस ऑफ सेफ्टी की दीवारें ऊंची,जवाबदेही नीची

दीवार फांद गए 15 अपचारी किशोर,व्यवस्था सोती रही

25 की क्षमता, 36 निरुद्ध: अंबिकापुर प्लेस ऑफ सेफ्टी में बड़ा सुरक्षा संकट

8 लौटे, 7 अब भी फरार: जवाबदेही से क्यों भाग रहा तंत्र ?

निगरानी और प्रबंधन पर आरोप

सूत्रों के हवाले से प्रभारी अधीक्षक की नियमित उपस्थिति और निगरानी पर प्रश्न उठे हैं; घटना के समय अनुपस्थिति और बाद में कागजी औपचारिकताओं को लेकर भी चर्चा है (इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि शेष है),यदि आकस्मिक निरीक्षण, नियमित ऑडिट और जवाबदेही तंत्र सख्त होते,तो क्या 15 किशोरों की सामूहिक फरारी संभव थी?

जांच टीम गठित,पर रिपोर्ट लंबित

घटना के बाद अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की गई है,हालांकि,अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई,ऐसे में यह आश्चंका भी उठ रही है कि कहीं मामला केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रह जाए, जांच का दायरा व्यापक होना चाहिए-क्षमता से अधिक निरुद्धीकरण की अनुमति किसने दी? सुरक्षा मानकों का अनुपालन क्यों नहीं हुआ? स्टाफिंग और प्रशिक्षण की वास्तविक स्थिति क्या है? काउंसलिंग और रिस्क असेसमेंट के रिकॉर्ड क्या कहते हैं?

पुलिस की कार्रवाई...

गांधीनगर थाना की पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और परिजनों/स्थानीय स्रोतों के माध्यम से तलाश जारी है, 7 किशोरों का अब भी फरार रहना कानून-व्यवस्था के साथ-साथ समुदाय की सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है।

पूर्व घटनाएं और सबक...

सूत्रों का दावा है कि पहले भी फरारी की घटनाएं सामने आई थीं, यदि यह सही है, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए? या हर घटना के बाद एक नई फाइल खुलती है और कुछ समय बाद बंद हो जाती है?



-न्यूज डेस्क-

अंबिकापुर,23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

गंगापुर बिशुनपुर स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी से 16 फरवरी सोमवार रात 15 अपचारी किशोरों का एक साथ दीवार फांदकर फरार होना पूरे बाल संरक्षण तंत्र पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा गया है, पुलिस कार्रवाई में 6 किशोर पकड़े गए और 2 स्वयं लौट आए, लेकिन 7 अब भी

फरार बताए जा रहे हैं, घटना के एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी शेष किशोरों का सुराग न मिलना और जांच रिपोर्ट का लंबित रहना प्रशासनिक जवाबदेही को कटघरे में खड़ा कर रहा है,इतने संवेदनशील संस्थान से एक साथ 15 किशोरों का निकल जाना केवल सुरक्षा चूक नहीं, बल्कि पूरे बाल संरक्षण तंत्र की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह है।

जघन्य अपराध के मामले, फिर भी सुरक्षा हल्की ?

यहां 16-18 वर्ष आयु वर्ग के वे किशोर रखे जाते हैं जो हत्या,दुष्कर्म,लुट जैसे गंभीर अपराधों में निरुद्ध हैं, ऐसे मामलों में उच्च स्तरीय सुरक्षा, सक्रिय सीसीटीवी,कार्यशील अलार्म सिस्टम, नियमित रिस्क असेसमेंट और सतत काउंसलिंग अनिवार्य मानी जाती है, सवाल उठते हैं: क्या सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम काम कर रहे थे? क्या जोखिम आकलन नियमित हुआ? क्या आक्रामक/समूहगत व्यवहार के संकेत पहले से थे?

तीन गार्ड बनाम 15 किशोर: संसाधन या प्रशिक्षण की कमी ?

तीन गार्ड 15 किशोरों को नहीं रोक पाए—यह नीयत से अधिक स्टाफिंग, प्रशिक्षण और संसाधनों का प्रश्न है, क्या रात्रि पाली में अतिरिक्त सुरक्षा का प्रावधान था? क्या गार्डों को भीड़ नियंत्रण और संकट प्रबंधन का प्रशिक्षण मिला? क्या मानक स्टाफिंग का पालन हो रहा था?

क्षमता से अधिक निरुद्धीकरण: 25 की जगह 36 ?

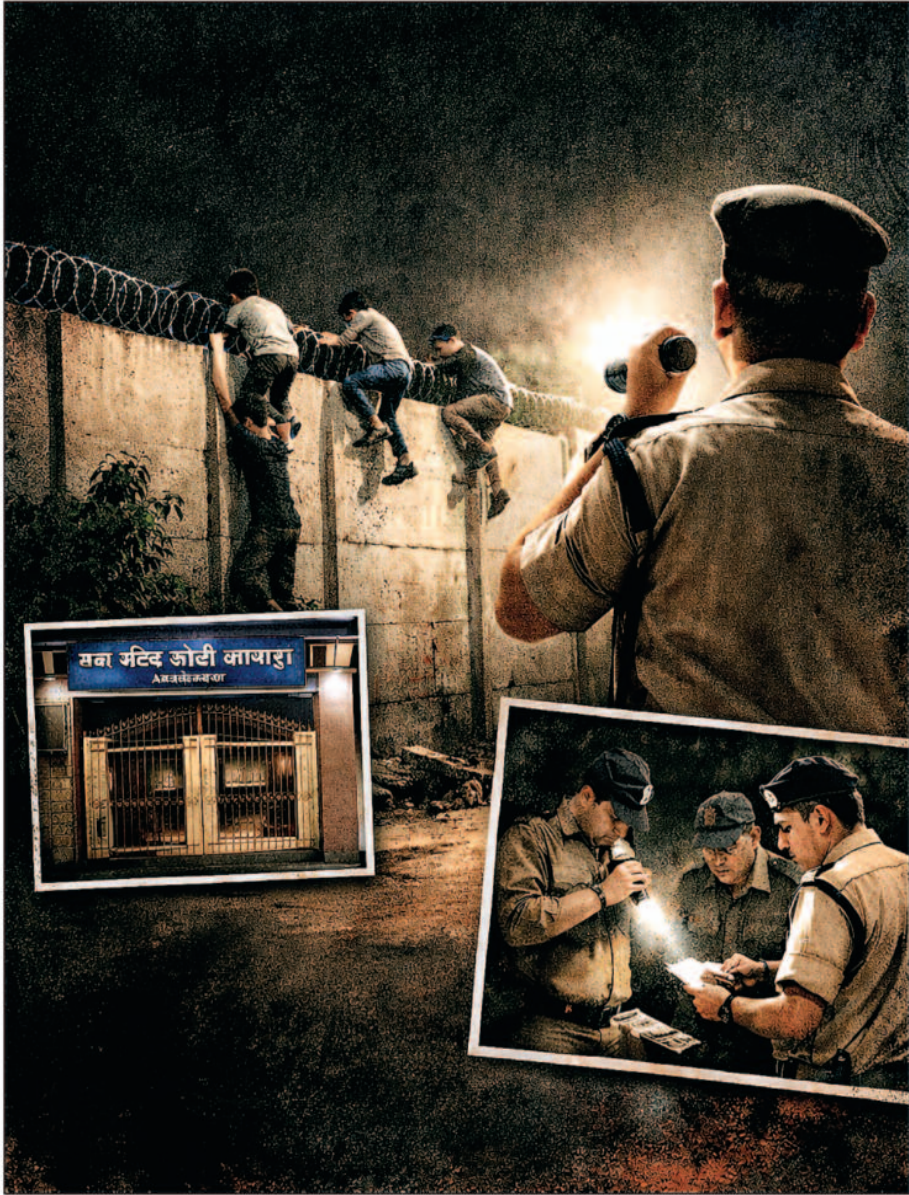
विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि इस प्लेस ऑफ सेफ्टी की स्वीकृत क्षमता 25 है, जबकि अंदर 26 से 36 तक अपचारी किशोर रखे गए, क्या यह अस्थायी व्यवस्था थी या नियमित प्रथा? नियमित निरीक्षण में यह संख्या दर्ज हुई या अनदेखी की गई? क्षमता से अधिक निरुद्धीकरण सुरक्षा, निगरानी और काउंसलिंग—तीनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

सुरक्षा गृह या खुला मैदान ? एक साथ 15 अपचारी फरार

जघन्य अपराध के किशोर निकले बाहर,बाल संरक्षण तंत्र पर सवाल

अंबिकापुर प्लेस ऑफ सेफ्टी कांड: लापरवाही या लीपापोती की तैयारी ?

तीन गार्ड,15 अपचारी और ढहती सुरक्षा—कौन जिम्मेदार ?



बड़ा सवाल: प्लेस ऑफ सेफ्टी या कागजी सुरक्षा ?

जब एक ही रात में 15 अपचारी किशोर निकल जाएं, तो यह दीवार की कमजोरी नहीं, व्यवस्था की दरार दिखाता है, बाल संरक्षण कोई विभागीय मद नहीं—यह समाज के भविष्य की सुरक्षा है, अब देखना यह है कि— क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या सुरक्षा ढांचा पुनर्गठित होगा? क्या क्षमता, स्टाफिंग और प्रशिक्षण मानकों की सख्त समीक्षा होगी? फिलहाल सबसे अहम प्रश्न वही है: 8 की वापसी के बाद भी 7 अपचारी किशोर कहाँ हैं, और उन्हें वापस लाने में इतनी देरी क्यों? जवाब केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच और ठोस सुधारात्मक कदमों से आएगा।

लापरवाही किसकी ?

सूत्रों के अनुसार,घटना के समय प्लेस ऑफ सेफ्टी के अधीक्षक बिना पूर्ण सूचना के अनुपस्थित थे, दावा यह भी किया जा रहा है कि घटना के बाद अनुपस्थिति को लेकर आवेदन बैंक डेट में दिया गया। यदि यह तथ्य सही हैं,तो यह एक अत्यंत संवेदनशील संस्थान में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मामला बनता है।

जांच टीम गठित,पर रिपोर्ट लंबित

घटना के बाद अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की गई है। हालांकि, अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि—क्या जांच निष्पक्ष होगी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? या फिर मामला लीपापोती की भेंट चढ़ जाएगा?

एक साथ 15 अपचारी बालकों का फरार होना

किसी भी प्लेस ऑफ सेफ्टी से एक साथ 15 अपचारी बालकों का फरार हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रश्नचिन्ह है,इतनी बड़ी चूक के बावजूद अब तक स्पष्ट जवाबदेही तय न होना विभागीय कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है।

प्रशासन की चुप्पी क्यों ?

एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, 7 अपचारी बालक अब भी लापता हैं,जांच रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं की गई, किसी भी अधिकारी पर ठोस कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई, इतने संवेदनशील मामले में प्रशासन की सुस्ती और अस्पष्टता चिंताजनक है। यह केवल सुरक्षा चूक का मामला नहीं, बल्कि नाबालिगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।

आगे क्या ?

अब देखना यह होगा कि जांच टीम अपनी रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष देती है, क्या अधीक्षक की भूमिका पर स्पष्ट निर्णय होगा? या फिर विभागीय स्तर पर केवल औपचारिक कार्रवाई कर मामले को शांत करने की कोशिश की जाएगी? फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न यही है—आखिर 7 अपचारी बालक कहाँ हैं, और उन्हें वापस लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है?

घटना कैसे हुई ?

सूत्रों के अनुसार 16 फरवरी रात करीब 9 बजे भोजन के बाद किशोरों को कमरों में ले जाया जा रहा था, इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात तीन गार्डों को धक्का देकर कुछ किशोरों ने हमला किया और परिसर की दीवार फांदकर निकल गए,सबसे गंभीर पहलू यह रहा कि तत्काल हेडकाउंट और अलर्ट सिस्टम कितनी तेजी से सक्रिय हुआ—इस पर स्पष्टता नहीं है, जानकारी बाहर तब आई जब परिजनों से संपर्क किया गया,घटना रात की,संज्ञान सुबह का—क्या आपातकालीन प्रोटोकॉल पर्याप्त था?

कठौतिया की 'सूखी डबरी' पर सवाल: बिना जल स्रोत बने पर्कोलेशन टैंक में लाखों खर्च,जांच की मांग तेज



-संवाददाता-

मनंदरगढ़ (एमसीबी), 23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

एमसीबी जिले की ग्राम पंचायत कठौतिया में निर्मित एक डबरी

(पर्कोलेशन टैंक) को लेकर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, जल संरक्षण और भू-जल पुनर्भरण के उद्देश्य से बनाए गए इस ढांचे पर लगभग सात लाख रुपये से अधिक की

राशि खर्च दर्शाई गई है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि यह संरचना वर्तमान में अनुपयोगी पड़ी है और अपेक्षित लाभ नहीं दे पा रही है।

व्यय विवरण और पारदर्शिता

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार:
5,32,257 सामग्री मद में व्यय
1,56,831 मजदूरी मद में व्यय
कुल मिलाकर लगभग 6.89 लाख की राशि खर्च दर्शाई गई है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि...

माप पुस्तिका की जांच हो

तकनीकी स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा की जाए

कार्यस्थल निरीक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए

ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खर्च की गई राशि निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग की गई या नहीं।

स्थल चयन पर तकनीकी आपत्ति

ग्रामीणों के अनुसार जिस स्थान पर डबरी का निर्माण किया गया है,वह क्षेत्र पथरीला और अपेक्षाकृत ऊँचाई पर स्थित है। आसपास न तो कोई स्थायी जल स्रोत दिखाई देता है और न ही प्राकृतिक जल प्रवाह की स्पष्ट दिशा, ऐसे में वर्षा जल संचयन की संभावना सीमित बताई जा रही है, विशेषज्ञों का मानना है कि पर्कोलेशन टैंक निर्माण से पूर्व निम्न बिंदुओं का अध्ययन आवश्यक होता है: स्थल का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, जल प्रवाह का आकलन, मिट्टी की जलधारण क्षमता, भू-जल स्तर का पूर्व परीक्षण, यदि इन पहलुओं की अनदेखी हुई है,तो निर्माण की उपयोगिता पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं।

निर्माण पूर्णता पर विवाद

निर्माण स्थल पर लगे सूचना पट्ट के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि 05 फरवरी 2026 अंकित बताई गई है। हालांकि, ग्रामीणों का दावा है कि संरचना अधूरी अथवा तकनीकी रूप से अपूर्ण प्रतीत होती है। उनका कहना है कि यदि कार्य पूर्ण घोषित किया गया है, तो उपयोगिता प्रमाणन और गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

अपेक्षित लाभ और वर्तमान स्थिति

पर्कोलेशन टैंक से सामान्यतः निम्न लाभ अपेक्षित होते हैं, वर्षा जल संचयन, भू-जल स्तर में सुधार, सिंचाई सुविधा में वृद्धि, मत्स्य पालन जैसी आयवर्धक गतिविधियों की संभावना, लेकिन स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वर्तमान स्थिति में न तो जल संचयन हो रहा है और न ही किसानों को कोई प्रत्यक्ष लाभ मिल पा रहा है।

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग की है, उनका कहना है कि यदि स्थल चयन या निर्माण में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित इंजीनियरों, तकनीकी सहायकों और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय की जानी चाहिए, जल संरक्षण योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, यदि इन योजनाओं का क्रियान्वयन वैज्ञानिक आधार पर न हो, तो इससे न केवल सरकारी धन का अपव्यय होता है, बल्कि किसानों की अपेक्षाओं को भी ठेस पहुंचती है।

निगाहें प्रशासन पर

कठौतिया की यह डबरी अब जल संचयन से अधिक प्रशासनिक जवाबदेही का विषय बन चुकी है, अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, क्या तकनीकी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, या मामला औपचारिक कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा? ग्रामीणों की मांग स्पष्ट है: जल संरक्षण योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

रेबीज मुक्त सूरजपुर की ओर बड़ा कदम

श्वानों के स्टरलाइजेशन व टीकाकरण का विशेष अभियान प्रारंभ



-संवाददाता-

सूरजपुर,23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिले में जनस्वास्थ्य और पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए, पशुधन विकास विभाग सूरजपुर द्वारा पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत श्वानों के स्टरलाइजेशन (नसबंदी) एवं रेबीज टीकाकरण का व्यापक अभियान प्रारंभ किया गया है,

यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2025 में सु-मोटो रिट-पिटोरशन में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संचालित किया जा रहा है, विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह अभियान चरणबद्ध तरीके से पूरे जिले में चलाया जाएगा, जिसमें शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों को भी शामिल किया गया है।

नागरिकों से अपील

पशुधन विकास विभाग ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है, अपने पालतू कुत्ते का नियमित टीकाकरण कराएं, नसबंदी अभियान में सहयोग दें, अभियान टीम को कार्य करने में बाधा न पहुंचाएं, बच्चों को आवाज श्वानों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के प्रति जागरूक करें, विभाग का कहना है कि प्रशासनिक प्रयास तभी सफल होंगे जब समाज भी सक्रिय भागीदारी निभाएगा।

जनस्वास्थ्य की दिशा में सकारात्मक पहल

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह अभियान नियमित और प्रभावी रूप से संचालित होता रहा, तो आने वाले वर्षों में सूरजपुर जिले को रेबीज मुक्त क्षेत्र बनाया जा सकता है, यह पहल न केवल मानव जीवन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पशु कल्याण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में भी एक सराहनीय कदम है।

अभियान की आवश्यकता क्यों ?

पिछले कुछ वर्षों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवाज श्वानों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, इससे श्वान काटने की घटनाओं में वृद्धि, रेबीज संक्रमण का खतरा, सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा की भावना जैसी समस्याएं सामने आ रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रशासन ने वैज्ञानिक और मानवीय तरीके से समस्या के समाधान का निर्णय लिया है, स्टरलाइजेशन (नसबंदी) के माध्यम से श्वानों की संख्या नियंत्रित होगी, वहीं रेबीज टीकाकरण से संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

रेबीज: एक जानलेवा बीमारी

विशेषज्ञों के अनुसार रेबीज एक वायरल बीमारी है, जो मनुष्य और पशुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, एक बार इसके लक्षण प्रकट हो जाने पर उपचार लगभग असंभव हो जाता है, इसलिए रोकथाम ही इसका एकमात्र प्रभावी उपाय है।

यदि किसी को पशु काट ले तो क्या करें ?

पशुधन विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने निम्न सावधानियां बताई हैं, घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से कम से कम 10-15 मिनट तक धोएं,एंटीसेप्टिक लगाएं,तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, डॉक्टर की सलाह अनुसार एंटी-रेबीज वैक्सीन अवश्य लगाएं, घरेलू उपचार या झाड़ू-फूंक जैसे उपायों से बचने की सलाह दी गई है।

अभियान की कार्यप्रणाली

विभिन्न क्षेत्रों में विशेष टीमों द्वारा आवाज श्वानों को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाएगा, पशु चिकित्सकों की निगरानी में स्टरलाइजेशन किया जाएगा, रेबीज टीकाकरण कर उन्हें निर्धारित समय बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, पालतू श्वान मालिकों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान पूरी तरह मानवीय और पशु संरक्षण नियमों के अनुरूप संचालित होगा।



सहकारिता विभाग में चयनात्मक कार्रवाई का विवाद

छह नामों की एफआईआर पर निशाने पर एक ही क्यों ?

छः नामों की एफआईआर, कार्रवाई एक पर...सहकारिता विभाग में चयनात्मक सख्ती ?

चार साल बाद जागा विभाग: आखिर निशाने पर सिर्फ एक ही क्यों ?

सहकारिता न्यायालय में सवाल की गुंज : छह आरोपी,पर जिम्मेदार एक ?

एफआईआर में छह, विभागीय चार में एक—क्या है अंदर की कहानी ?

देरी से कार्रवाई,एक पर सख्ती...क्या सहकारिता तंत्र में संतुलन बिगड़ा ?

संयुक्त आयुक्त के फैसले पर उठे सवाल: समान कार्रवाई या चयनात्मक प्रहार ?

धान खरीदी प्रकरण: चार साल की खामोशी के बाद एक पर गाज क्यों ?

सहकारिता विभाग में 'टारगेटेड एक्शन' की चर्चा तेज

एफआईआर 2022 की, कार्रवाई 2026 में—और दायरा सीमित क्यों ?

सहकारिता तंत्र में पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न: बाकी पांच कहाँ है ?

—ऑफर पाण्डेय—
सुरजपुर, 23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर में पदस्थ संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सुनील तिवारी द्वारा की गई हालिया कार्रवाई ने सहकारिता तंत्र में नई बहस छेड़ दी है, मामला वर्ष 2019-20 की धान खरीदी से जुड़ा है, जिसमें अनियमितताओं के आरोपों पर 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी, उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार इस एफआईआर में छह नाम शामिल थे, लेकिन विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई सामने आई, उसमें मुख्य रूप से एक कर्मचारी—समिति स्तर के प्रभारी प्रबंधक—को केंद्र में रखा गया, यही वह बिंदु है जहां से विवाद और सवालों की श्रृंखला शुरू होती है।

सहकारिता विभाग की साख केवल कठोर आदेशों से नहीं, बल्कि संतुलित और पारदर्शी कार्रवाई से बनती है, यदि छह नाम एफआईआर में हैं, तो कार्रवाई की रोशनी भी समान रूप से पड़नी चाहिए। अन्यथा चयनात्मक निर्णयों की धारणा प्रशासनिक विश्वसनीयता को कमजोर करती है, अब निगाहें इस बात पर हैं कि विभाग शेष आरोपियों की स्थिति स्पष्ट करेगा या नहीं, और क्या भविष्य में इस प्रकार के मामलों में एकरूप और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाएगी।



पारदर्शिता और समानता पर पूरा प्रकरण तीन मूल सवालों पर आ टिकता है...

1. क्या विभागीय कार्रवाई समयबद्ध और निष्पक्ष थी ?
2. क्या सभी आरोपियों के विरुद्ध समान प्रक्रिया अपनाई गई ?
3. क्या निर्णय प्रक्रिया बाहरी प्रभावों से मुक्त है ? जब तक इन प्रश्नों के आधिकारिक और तथ्यात्मक उत्तर सार्वजनिक नहीं होते, तब तक यह मामला सहकारिता तंत्र में अविश्वास और असंतोष का विषय बना रहेगा।



एफआईआर 2022 की, सक्रियता 2026 में...

प्रश्न यह है कि यदि 05 अप्रैल 2022 को एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, तो विभागीय कठोर कार्रवाई में लगभग चार वर्ष का अंतर क्यों? क्या जांच लंबित थी? क्या विभागीय स्तर पर कोई आंतरिक परीक्षण चल रहा था? या फिर मामला फाइलों में दबा रहा और अब अचानक प्रार्थमिकता में आ गया? समय-सीमा में यह अंतर प्रशासनिक सुस्ती या परिस्थितिजन्य विवशता—दोनों में से किसे दर्शाता है, यह स्पष्ट होना चाहिए।

छह आरोपी, कार्रवाई एक पर...

एफआईआर में छह नाम दर्ज बताए जाते हैं, ऐसे में यदि विभागीय पत्राचार और चेतावनी मुख्य रूप से एक व्यक्ति पर केंद्रित है, तो शेष पांच की स्थिति क्या है? क्या वे निर्दोष पाए गए? क्या उनके विरुद्ध अलग प्रक्रिया चल रही है? या फिर जांच की दिशा ही बदल दी गई? प्रशासनिक सिद्धांत कहता है कि जवाबदेही सामूहिक हो तो कार्रवाई भी संतुलित और समान होनी चाहिए। चयनात्मक सख्ती से पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगता है।

पत्र की भाषा और जिम्मेदारी का स्थानांतरण

विभागीय आदेश में यह भी उल्लेखित है कि यदि आरोपी कर्मचारी को सेवा से पृथक् नहीं किया गया और भविष्य में कोई गड़बड़ी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की मानी जाएगी। यह निर्देश असामान्य रूप से कठोर माना जा रहा है, सवाल उठता है—क्या विभाग अपने पूर्व विलंब की भरपाई तत्कालिक कठोरता से कर रहा है?

क्या निर्णय प्रक्रिया प्रभावित है ?

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि सहकारिता विभाग के न्यायालयीन माहौल में बैंक कर्मचारी और कुछ प्रभावशाली समूहों की उपस्थिति प्रभाव डालती है, आरोप यह भी है कि कार्यालय में बैठकर अनौपचारिक चर्चाएं निर्णयों को दिशा देती हैं, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन यदि ऐसा वातावरण बनता है तो यह संस्थागत निष्पक्षता के लिए चिंताजनक संकेत है।

सेवानिवृत्ति समीप—क्या प्रार्थमिकताएं बदलीं ?

संयुक्त आयुक्त के कार्यकाल के अंतिम चरण में होने की बात भी चर्चा में है, कुछ लोग इसे तेज निर्णयों की वजह मानते हैं, तो कुछ इसे चयनात्मक सक्रियता से जोड़कर देखते हैं, परंतु यह केवल अटकलें हैं, किसी भी अधिकारी के निर्णय को तथ्य और दस्तावेज के आधार पर ही परखा जाना चाहिए।

फेडरेशन और आंतरिक राजनीति का कोण

सहकारिता तंत्र में कर्मचारी-अधिकारी समूहों के बीच शक्ति संतुलन भी इस मामले से जुड़ा माना जा रहा है, यदि किसी कार्रवाई के बाद कुछ वर्ग विशेष में उत्साह दिखता है, तो यह संकेत देता है कि आंतरिक समीकरण पहले से मौजूद थे। क्या यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया थी, या फिर संगठनात्मक दबावों का परिणाम—यह स्पष्ट होना शेष है।

बैकुण्ठपुर में जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग सम्पन्न, संगठन से राष्ट्र निर्माण का संकल्प

पंडित दीनदयाल उपाध्याय 'प्रशिक्षण महा-अभियान' का आगाज



—संवाददाता—
कोरिया, 23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत भाजपा जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्रों पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम मुख्य रूप से रामलखन पैकरा एवं भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 'प्रशिक्षण महा-अभियान' के माध्यम से भाजपा संगठनात्मक मजबूती के साथ वैचारिक सुदृढ़ता पर भी जोर दे रही है, बैकुण्ठपुर में आयोजित यह जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रमों में नई ऊर्जा और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देता है।

प्रथम सत्र: विचारधारा और 'पंच परिवर्तन' पर मार्गदर्शन

प्रथम सत्र में अतिथि स्वागत, वंदेमातरम् एवं वर्ग गीत के पश्चात मुख्य वक्ता रामलखन पैकरा ने

अन्य सत्रों में विशेषज्ञ मार्गदर्शन

द्वितीय सत्र: शारदा गुप्ता ने प्रशिक्षण कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की।
तृतीय सत्र: सोनालाल राजवाड़े ने नवाचार पर मार्गदर्शन दिया।
चतुर्थ सत्र: विभिन्न वक्ताओं ने संगठनात्मक सुदृढ़ता और जनसंपर्क के विषयों पर विचार साझा किए, समापन सत्र में अतिथियों को स्थानीय उत्पाद सोनहनी, कोरिया मोदक एवं मिलेट्स कुकीज भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। स्थानीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा हस्तनिर्मित पुष्पगुच्छ से अतिथियों का स्वागत किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

कार्यकर्ताओं को पंच परिवर्तन विषय पर विस्तार से संबोधित किया। उन्होंने संगठन की कार्यपद्धति, विचारधारा और प्रत्येक कार्यकर्ता के दायित्वों पर प्रकाश डालते हुए कहा—जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होगा, तभी राष्ट्र समृद्ध और उन्नत बनेगा। स्वदेशी के आचरण से आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन बढ़ता है, जनहितकारी शासन और जनोन्मुख प्रशासन परस्पर सहयोग से ही राष्ट्रबल को वैभवशाली बनाते हैं।

संगठन से राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य

जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रदेशभर में महा-प्रशिक्षण अभियान

प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन की विचारधारा, आचार और व्यवहार को आत्मसात करने का आह्वान किया।

बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े, नगर पालिका अध्यक्ष अरुण जायसवाल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता यादव, भाजयुमो जिलाध्यक्ष सतेन्द्र राजवाड़े सहित विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बिलासपुर में पत्रकारों का महाकुंभ : सुबोध तिवारी फिर बने प्रदेश अध्यक्ष

कृष्णा सिंह बाबा कार्यकारी अध्यक्ष, नामदेव भवन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ निर्वाचन



—संवाददाता—
बिलासपुर / कोरिया, 23 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के प्रमुख संगठन छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ (पंजीयन क्र. 411) की प्रदेश कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक बिलासपुर के नूतन कॉलोनी स्थित नामदेव भवन में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई। प्रदेशभर से आए पत्रकारों की उपस्थिति में श्री सुबोध तिवारी को सर्वसम्मति से

150 से अधिक पत्रकारों की उपस्थिति

बैठक में प्रदेश के लगभग सभी जिलों से 150 से अधिक पत्रकार उपस्थित रहे। नई कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गुंज उठा, निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह ने नवगठित कार्यकारिणी को बधाई देते हुए संगठन की एकजुटता की सराहना की।

पुनः प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन चुनाव अधिकारी विनोद सिंह की देखरेख में हुआ। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्णा

सिंह बाबा और वरिष्ठ सदस्य श्री राधेश्याम कोरी सहित उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से समर्थन प्रदान किया। प्रदेश महासचिव श्री शशांक दुबे की सक्रिय भूमिका में निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की गई, बिलासपुर की इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया कि संगठन केवल नाम का नहीं, बल्कि सक्रिय और संगठित शक्ति है, सुबोध तिवारी के पुनर्निर्वाचन के साथ ही छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने एक बार फिर एकता और लोकतांत्रिक परंपरा का परिचय दिया है। आने वाले समय में संगठन पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा और कल्याण को लेकर और अधिक मुखर भूमिका निभाएगा।

प्रमुख पदाधिकारियों के ओजस्वी उद्बोधन

हमारी प्रार्थमिकता पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान- सुबोध तिवारी

नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सुबोध तिवारी ने कहा—मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं पूरे प्रदेश के पत्रकार साथियों का आभारी हूँ। हमारी प्रार्थमिकता केवल पद नहीं, बल्कि प्रत्येक पत्रकार की सुरक्षा और सम्मान है। शासन-प्रशासन के समक्ष पत्रकारों की मांगों को पूरी प्रखरता के साथ रखेंगे।

संगठन एक परिवार है: कृष्णा सिंह बाबा

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा सिंह बाबा ने कहा—यह संगठन परिवार की तरह है। सुबोध जी के नेतृत्व में हमने कई मील के पथर तय किए हैं। अब ग्रामीण स्तर तक के पत्रकारों को मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प है।

नियमावली ही हमारी शक्ति: शशांक दुबे

प्रदेश महासचिव शशांक दुबे ने पारदर्शिता और अनुशासन पर जोर देते हुए कहा—निर्वाचन सफल जारी करने से लेकर इस आयोजन तक, हर प्रक्रिया नियमों के अनुरूप हुई। संगठन की नियमावली ही हमारी असली ताकत है।

संगठन ही साथियों का कवच: राधेश्याम कोरी

वरिष्ठ सदस्य राधेश्याम कोरी ने कहा—पत्रकारिता चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में यह संघ साथियों के लिए कवच का कार्य करता है। नेतृत्व सही हाथों में है।

एकता से नई ऊर्जा: महेश तिवारी

वरिष्ठ सदस्य महेश तिवारी ने कहा—बिलासपुर की धरती से लिया गया संकल्प पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार जगत में नई ऊर्जा भरेगा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा... वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण

कवासी लखमा ने भाजपा नेताओं को गले लगाया,अजय चंद्राकर ने सदन में थाप-थापाई पीट

रायपुर,23 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र को शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ,जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उनके मुताबिक रायपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया और पिछले दो सालों में 532 नक्सली न्यूट्रलाइज्ड किए जा चुके हैं। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सदन पहुंचे पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा नेताओं से गले मिलकर मुलाकात की। उन्होंने अजय चंद्राकर,रामविचार नेताम और धर्मजीत सिंह को गले लगाया। इस दौरान चंद्राकर ने लखमा की पीठ थाप-थापाई। 25 फरवरी को इस अभिभाषण पर चर्चा होगी। वित्तमंत्री ओ. पी. चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। बजट,वित्तीय वर्ष 2026-27 का, 24 फरवरी को पेश किया जाएगा।

प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 रुपए पहुंचने का अनुमान

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत से अधिक की रफ्तार से बढ़ सकती है। स्थिर कीमतों (आधार वर्ष 2011-12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8.11 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। वहीं, प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सोमवार को विधानसभा में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री ओ. पी. चौधरी ने पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 में राज्य की लक्ष्य स्थिर कीमतों पर बढ़कर 3,58,293 करोड़ रुपये और चालू कीमतों पर



जिलों में नालंदा लाइब्रेरी, रिंग रोड बनेगी

सत्र से पहले स्पीकर रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में हुई। बैठक में सीएम साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत डिटी सीएम अरुण साव समेत मंत्री और समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस बार का बजट गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और उद्योग पर केंद्रित रहेगा, साथ ही युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए खास योजनाएं लाई जाएंगी। जिलों में नालंदा लाइब्रेरी, शहरों में स्टेडियम और रिंग रोड बनाए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पीएम सूर्यधर और आयुष्मान योजनाओं के लिए भी बजट में बड़ा प्रावधान प्रस्तावित है।

6,31,291 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। चालू कीमतों पर वृद्धि दर 11.57 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सर्वेक्षण में राज्य की वृद्धि को तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है:

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य): 7.49% वृद्धि

- उद्योग क्षेत्र (खनन, निर्माण, विनिर्माण, बिजली,गैस, जल आपूर्ति): 7.21% वृद्धि

- सेवा क्षेत्र: 9.11% वृद्धि

चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय इस वित्तीय वर्ष में 1,79,244 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है,जो पिछले वर्ष 1,62,848 रुपये थी। इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय में 10.07 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी।



दो अहम विधेयक भी सूची में...

इस सत्र में दो महत्वपूर्ण विधेयक भी लाए जाने की सूचना है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 और छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2026। इन विधेयकों को लेकर राजनीतिक बहस की संभावना जताई जा रही है।

सवालों और प्रस्तावों की भरमार

बजट सत्र के लिए अब तक 2813 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1376 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम 139 के तहत 1 अविलंबनीय चर्चा, 13 अशासकीय संकल्प, शून्यकाल की 9 सूचनाएं और 112 याचिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। इससे साफ है कि सत्र के दौरान सरकार को कई मुद्दों पर जवाब देना होगा।

एक साल बाद सदन में वापसी

शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा करीब एक साल तक जेल में रहे। इस दौरान वे विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सके। अब उच्च न्यायालय की ओर से 3 फरवरी को उन्हें अंतरिम जमानत दी

गई है। इसके बाद विधानसभा की ओर से 7 फरवरी को उनका अभिमत मांगा गया और 2026 में उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। अब उन्हें तय शर्तों के आधार पर सत्र में शामिल होने की अनुमति दी गई। विधानसभा की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कवासी लखमा को जब भी सदन में आना या जाना

होगा, इसकी जानकारी पहले से विधानसभा सचिव को देनी होगी। उनकी आवाजही पर नजर रहेगी और पूरा कार्यक्रम औपचारिक रूप से दर्ज किया जाएगा। उन्हें अपने निवास क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति नहीं होगी। यानी वे सत्र के दौरान किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि या क्षेत्रीय कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। उनकी मौजूदगी केवल विधानसभा परिसर और सत्र की कार्यवाही तक सीमित रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण शर्त 'नो स्पीच' से जुड़ी है। उन्हें अपने ऊपर चल रहे मामले के संबंध में किसी भी प्रकार का बयान देने या चर्चा करने की अनुमति नहीं होगी।

वे बजट या अन्य सामान्य विषयों पर चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन अपने केस से जुड़े किसी भी मुद्दे पर न तो बोलेंगे और न ही टिप्पणी करेंगे। यदि उन्होंने इन शर्तों का उल्लंघन किया तो उनकी अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सदन में भी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी।

राजनीतिक तौर से अस्म सत्र

शुरू हुआ यह बजट सत्र वित्तीय दुर्घटि से तो महत्वपूर्ण है ही, राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। सरकार 2026-27 के बजट के जरिए अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखेगी, वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके साथ ही कवासी लखमा की सशर्त मौजूदगी भी सत्र के दौरान चर्चा का विषय बनी रहेगी। अगले एक महीने तक राज्य की राजनीति का केंद्र विधानसभा ही रहेगा।

ओडिशा में रायपुर पुलिस की रेड,गांजा एजेंट गिरफ्तार..

तस्कर से पूछताछ के बाद एक्शन,खाते में पैसे लेकर सप्लाई कराने में निभाता था भूमिका

रायपुर,23 फरवरी 2026।

रायपुर पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में ओडिशा से एक और आरोपी राजकिशोर बेहरा उर्फ मिलन (31) को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस और एससीपी ने संयुक्त कार्रवाई की है। आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल जब्त किया गया है। दरअसल, 14 फरवरी 2026 सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि,केनाल रोड स्थित दुर्गा मंच के पीछे खाली मैदान में कार सवार दो व्यक्ति अवैध रूप से गांजा रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने दृष्टि देकर हथियार उर्फ त्रुषि सरोज और हिमांशु दासले को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 50 किलोग्राम गांजा और 2 लाख बरामद हुआ था। इस मामले में आगे की जांच के दौरान फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर अन्य सलिस आरोपियों की तलाश की जा रही थी। पूछताछ



में सामने आया कि राजकिशोर बेहरा उर्फ मिलन पैडलर के रूप में काम करता था। वह अपने खाते में पैसे लेकर मादक पदार्थ की सप्लाई कराने में भूमिका निभाता था। पुलिस ने ओडिशा के फुलवानी जिले के बालीगुड़ा थाना क्षेत्र स्थित उसके निवास से आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 88/2026 के तहत धारा 20(सी) और 29 नार्कोटिक एक्ट में कार्रवाई की गई है।

नेटवर्क से जुड़े कई लोगों की तलाश जारी

सिविल लाइन थाना प्रभारी यमन देवांगन ने बताया कि, आरोपी से पूछताछ के बाद इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। सिडिकेट में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गांजा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

विधानसभा के सदस्यों के लिए ब्रह्मा भोजन का आयोजन सुंदर और प्रेरणादायी परंपरा : सीएम साय

रायपुर,23 फरवरी 2026।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नया रायपुर स्थित शांति सरोवर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानित सदस्यों के लिए प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नैह मिलन एवं ब्रह्मा भोजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने ब्रह्माकुमारी बहनों के स्नेह, आत्मीयता और सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि बहनों के प्रेम और आदर से हम सब अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बड़े स्नेह के साथ विधानसभा के सदस्यों के लिए ब्रह्मा भोजन का आयोजन एक सुंदर और प्रेरणादायी परंपरा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्था द्वारा समाज में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मिक शांति के प्रसार की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शांति सरोवर और शांति शिखर जैसे आध्यात्मिक केंद्रों में सदैव सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। संस्था का 137 से अधिक देशों में विस्तार होना अत्यंत सुखद और प्रेरक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अनेक जनकल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में जनजागृति लाने का कार्य कर रहा है। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से संशक्त बनाने में संस्था की भूमिका उल्लेखनीय है। जनजातीय क्षेत्रों में भी संस्था द्वारा सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों से स्थानीय लोगों को व्यापक लाभ मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ब्रह्माकुमारी बहनों के अतिथि बने



और पवित्र ब्रह्मा भोजन ग्रहण किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित कैबिनेट मंत्रीगण और सभी विधायकगणों ने भी ब्रह्मा भोजन का आनंद लिया। कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने मुख्यमंत्री एवं विधानसभा के सभी सदस्यों को माउंट आबू आने का आग्रह किया, जिसे मुख्यमंत्री साय ने सहर्ष स्वीकार करते हुए वहां आने की सहमति दी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप,कृषि मंत्री रामविचार नेताम,विधायक धरमलाल कौशिक सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्रह्माकुमारी परिवार की ओर से मृत्युंजय भाई,आत्म प्रकाश भाई,हेमलता दीदी, लता दीदी, आशा दीदी, सरिता दीदी एवं सविता दीदी सहित अन्य सदस्य कार्यक्रम में सहभागी रहे।

छत्तीसगढ़ बजट 2026...कांग्रेस विधायक दल की बैठक,सदन में सरकार को घेरने की बनी रणनीति,महंत बोले...कांग्रेस करेगी धर्मांतरण विधेयक का विरोध

रायपुर,23 फरवरी 2026।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट 2026 पेश होने की पूर्व संध्या प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत,पूर्व सीएम भूपेश बघेल,पीसीसी चीफ दीपक बैज,उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। कांग्रेस विधायकों ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है,जिसमें धर्मांतरण विधेयक का विरोध भी शामिल है। वहीं कांग्रेसियों ने विधायक लखमा को सत्र में शामिल होने की अनुमति के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह का आभार जताया। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बजट सत्र की रणनीति को लेकर जानकारी दी। सदन में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस बजट सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों को आक्रामक ढंग से उठाएगी। उन्होंने धान



इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति

कांग्रेस ने प्रशासनिक आतंकवाद,गुरूर में पुलिस प्रताड़ना से जुड़े आत्महत्या का मामला, एसडीएम से संबंधित विवाद,एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी और बिजली बिल दरों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। चरण दास महंत ने राज्य सरकार के आगामी तीसरे बजट पर निशाना साधते हुए इसे 'दुर्गति वाला बजट' करार दिया।

खरीदी में कथित अव्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि राज्य के इतिहास में ऐसी बर्दाश्तजामी पहले कभी नहीं देखी गई।

धर्मांतरण विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस

धर्मांतरण विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है, तो सरकार इस विषय पर कानून क्यों ला रही है। कांग्रेस इस विधेयक का विरोध करेगी।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर कांग्रेस के सवाल : नक्सलवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि सरकार एक ओर नक्सलियों के सफाई की बात कर रही है, लेकिन प्रभावित इलाकों के विकास को लेकर उसकी नीति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन क्षेत्रों में विकास कार्य आखिर कौन करेगा, सरकार या बड़े उद्योगपति? महंत ने कहा कि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है।

डीएमएफ फंड घोटाले में अनिल टुटेजा गिरफ्तार

डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई, कोर्ट ने 26 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा

रायपुर,23 फरवरी 2026।

छत्तीसगढ़ डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) घोटाला मामले में आरोपी पूर्व आईएसएस अनिल टुटेजा को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई ब्यूरो ने दर्ज अपराध की विस्तृत जांच के बाद की है। जांच के दौरान मिले डिजिटल सबूत, दस्तावेज और गवाहों के बयानों से यह सामने आया है कि आरोपी ने डीएमएफ फंड से जुड़े काम अपने परिचित लोगों और फर्मों को कमीशन लेकर दिलवाए। आरोप है कि उसने अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के जरिए भी अलग-अलग फर्मों को कमीशन लेकर डीएमएफ के काम आवंटित करवाए। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के



खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध प्रथम दृष्टया पाए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विधि अनुसार कोर्ट में पेश किया गया। जहां से 26 फरवरी 2026 तक की पुलिस रिमांड की अनुमति दी गई है। मामले की जांच

जारी है। प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है। केस में यह तथ्य निकल कर सामने आए हैं कि डिस्ट्रिक्ट मार्निंग फंड कोरबा के फंड से अलग-अलग टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर आर्थिक

अनियमितता पाई गई। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया। ईडी की जांच ने डीएमएफ घोटाले के तौर-तरीकों का खुलासा किया है। इसमें यह बात सामने आई है कि ठेकेदारों के बैंक खाते में जमा की गई राशि का बड़ा हिस्सा ठेकेदारों ने सीधे केश में निकाल लिया है। जांच के दौरान ईडी ने ठेकेदारों,सरकारी और उनके सहयोगियों के अगल-अगल ठिकानों पर रेड मारी थी। कोरबा में हुए 575 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफ) घोटाला मामले में महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। घूस लेने के लिए खर्च के नियम बदले गए। कलेक्टर को 40%, सीईओ 5%, एसडीओ 3% और सब इंसीनियर को 2% कमीशन मिला।

कर्रशन के लिए फंड खर्च के नियमों को बदला गया...

डीएमएफ के वर्क प्रोजेक्ट में कर्रप्शन के लिए फंड खर्च के नियमों को बदल गया था। फंड खर्च के नए प्रावधानों में मटेरियल सप्लाई, ट्रेनिंग, कृषि उपकरण, खेल सामग्री और मंडिकल उपकरणों की कैटेगरी को जोड़ा गया था, ताकि संशोधित नियमों के सहारे डीएमएफ के तहत जरूरी डेवलपमेंट वर्क को दरकिनार कर अधिकतम कमीशन वाले प्रोजेक्ट को अप्रुव किया जा सके। इसकी पुष्टि रायपुर कोर्ट में एंटी कर्रप्शन ब्यूरो (एसबीबी) की ओर से पेश किए गए 6 हजार पेज के चालान से हुई।

राष्ट्रपति की मुहर...छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की पैरवी करेंगे 36 वकील

रायपुर,23 फरवरी 2026।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के मुकदमों (करो से संबंधित मामलों को छोड़कर) की पैरवी के लिए 36 अधिवक्ताओं की नई सूची जारी कर दी गई है। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इन नियुक्तियों का आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह नियुक्तियां आगामी तीन वर्षों के लिए प्रभावी होंगी। सीनियर और सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल जारी आदेश के अनुसार, अधिवक्ताओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सीनियर पैनल काउंसिल की सूची में 8 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है। ये अनुभवी वकील महत्वपूर्ण और जटिल मुकदमों में केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल की इस श्रेणी में 28 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। ये अधिवक्ता केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की नियमित पैरवी करेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल,9 प्राचार्य और सहायक प्राध्यापकों का तबादला

रायपुर, 23 फरवरी 2026।

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक फेरबदल किया गया है।आदेश में प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापकों के तबादले किए गए हैं। 9 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित किया गया है।